class who would like to grow, not a monopoly in size as Shri Patodia has said but into a monopoly of control. They are seeking to cotrol every thing.

They would like to expand in all directions. They would not like to invest all their money in one concern. As the General Motors have done. they would like to expand in all directions to over 200 to 300 concerns and sell things at a very high price. They produce at a lower price and they charge a very high price. They do all that type of thing and maintain general incompetency in the country and take advantage of the sheltered market that we are maintaining in the country, not for the benefit of the growth of industry but for concerning the market to sell things at a very high price which Indian consumers are compelled to pay. This is the situation which can only be solved if we do not allow the exploitation of foreign exchange for unfruitful purposes and allow it to be used for only national useful purposes. Let us, if necessary, use the foreign exchange to import food, not under P. L. 480, rather than use it in a manner in which we are using, which is very harmful to the country and very bad for the future of the country.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the Half-an-hour discussion.

18.32 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Assignment of Miscellaneous Jobs to Jawans

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, संसद के पिछले अधिवेशन में जब सुरक्षा सम्बन्धी मामले की एक बहस मैंने उठाई थी तो उसी प्रसंग में एक चर्चा हुई थी कि सेना में जो हमारे जवान काम करते हैं, या जो मोर्चों पर रहकर देश की सेवा करते हैं, उनसे सेना के बड़े बड़े अधिकारी उनके कर्तव्य पालन के अतिरिक्त उनका प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिए भी करते हैं। उनके वे निजी कार्य यहां तक नीचे गिर गये हैं कि जूतों पर पालिश कराने से लेकर बच्चे खिलाने तक की सेवायें जवानों से लेते हैं। जब यह बात समाचार-पत्रों में उसी चर्चा के माध्यम से प्रकाशित हुई तो सेना के कुछ सैनिकों की ओर से पूरे दो पृष्ठ का उनकी कठिनाइयों सम्बन्धी एक पत्र मेरे पास आया। उस पत्र में जहां उन्होंने और बहुत सी कठिनाइयां लिखी हैं, उसमें एक विशेष पैराग्राफ मैं सुनाना चाहता हूं जिसने मुझे यहां पर इस प्रश्न को उठाने के लिए प्रेरित किया। जिसके इतने हल्के उत्तर की अपेक्षा मैं रक्षा मन्त्रालय से नहीं करता था कि इतनी उपेक्षा से रक्षा मन्त्रालय उसका उत्तर देगा। उन्होंने लिखा है :

> "एक सैनिक को सेवादार के रूप में बूट पालिश करने के लिए फौजी आदेश दिया जाता है। अगर आदेश की अवहेलना होती है तो उनको दंड दिया जाता है। किसी भी देश के कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो व्यक्ति अभियोग लगाता है वही उस हेतु दंड भी दे। सैनिक की आत्मा कुचली हुई है। क्या उसका मनोबल ऊंचा करने का यही तरीका है?"

जब यह पैराग्राफ इस पत्र में मैंने लिखा हुआ देखा तो मेरे मन पर बहुत बड़ी चोट लगी। मैंने फिर इस बात को रक्षा मन्त्रालय से प्रश्न के रूप में पूछा कि कहां तक इसमें वास्तविकता है ? इस प्रश्न का उत्तर रक्षा मन्त्रालय ने तीन पंक्तियों में दिया और यह लिखा कि इस प्रकार के कार्य उनसे न लिये जायं इस के आदेश पहले से ही दिए हुए हैं। फिर भी यदि कोई शिकायतें होती हैं तो उनका हम समुचित समाधान करते हैं। इतना कहकर रक्षा मन्त्रालय ने इस प्रश्न का टाल दिया। लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यह असन्तोष आज गम्भीर रूप धारण करने जा रहा है। सेना के अन्दर जवानों की इन कठिनाइयों की ओर यदि रक्षा मन्त्रालय या भारत सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया तो मुझे भय है कि यह विस्फोट किसी दिन दूसरा रूप न ले ले।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अंग्रेजों के जमाने में जो परम्परा सेना में थी, या अफ़सरों और जवानों के बीच में जो खाई थी, उसका कारण था। कारण यह था कि अंग्रेज़ जवानों को महसूस कराना चाहते थे कि हम तुम्हारे शासक हैं, तुम हमारे गुलाम हो हम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करते हैं। दूसरा, उन दोनों के बीच खाई का कारण था विदेशीपन वे भारतीयों की स्वाभिमान की भावना को मिटाना चाहते थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि स्वतन्त्र भारत में 22 वर्षों के बाद भी अभी तक सेनाओं में वह अभिशाप उसी प्रकार से क्यों जारी है। सभापति जी, आपको जान कर आश्चर्य होगा कि अबसे लगभग दस वर्ष पहले, रक्षा मन्त्री स्वयं मेरी इस बात की साक्षी देंगे. सिख रेजिमेन्ट के जवानों में इसी बात को लेकर कुछ प्रतिक्रिया हुई थी। उनका कहना था कि हम अफसरों के जूते पर पालिश नहीं करेंगे और रक्षा मन्त्रालय ने उस समय इस प्रकार के कुछ आदेश भी दिये थे। लेकिन जो और दूसरे जवान हैं उनसे अभी भी इस प्रकार के काम लिये जाते हैं। यों जूते पर पालिश करने का काम मुश्किल से एक डेढ़ मिनट का होता है। लेकिन अफ़सर लोग चाहते हैं कि आधे घंटे तक इस तरह से जूते रगड़ो कि अफसर का मुंह भी उसमें चमकने लगे। इस प्रकार की वह जूतों पर पालिश करवाते हैं, और भी दूसरी इसी प्रकार की सेवाय लेते हैं। तो क्या आप उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं, जिस दिन यह विस्फोट किसी और भयकर रूप में आप के सामने प्रकट हो तब समाधान ढूंढें? अच्छा यह है कि आप को अभी से उस का समाधान ढूंढना चाहिये और उसके लिये कुछ निश्चित रूप से आपको योजना बनानी चाहिये। न केवल जूतों पर पालिश करवाना या अफ़सरों की बीबियों और पत्नियों को बाज़ारों में सब्ज़ियां खरीदवाने के लिये ले जाना, या उनके बच्चों को खिलाने के लिये ले जाना, बल्कि स्थिति यहां तक हो गई है कि जो अफ़सरों के कैन्टूनमेंट में बंगले होते हैं, उन का काफ़ी बड़ा एरिया होता है, उनके बगीचों में पानी देने के लिये भी उनको प्रयोग किया जाता है। दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली के आसपास कुछ बड़े बड़े मिलिटरी आफ़िसर्स के फार्म हैं, जवानों से उन फार्मों पर ले जा कर, काम कराया जाता है। यानी उनका निजी आय के साधनों के लिये प्रयोग किया जाता है। अब आप अनुमान लगायें कि इस से क्या नुकसान हो रहा है? इस से सबसे बडा नुकसान यह हो रहा है कि जवान का वह समय जो उस को अपनी ट्रेनिंग के लिये लगाना चाहिये था या देश के लिये लगाना चाहिये था, वह नहीं लगा पा रहा है। एक ओर तो आप उनमें स्वदेशाभिमान को जगाना चाहते हैं और दूसरी ओर उस, के आत्माभिमान को इस प्रकार छोटे छोटे कामों को ले कर कुचलना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आज आप इस बात को देखिये कि इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ने से सेना में किस प्रकार की भावना जवानों के अन्दर आती चली जा रही है।

इस पत्र में उन्होंने कठिनाइयां लिखी हैं सैनिक वर्ग की ओर से उन्होंने समझदारी की जो अपना नाम या रैंक नहीं दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें लिखी हैं उन पर रक्षा मन्त्री महोदय, थोड़ा इस बात को अपने मस्तिष्क से हटा कर कि वह रक्षा मन्त्री हैं अपितु यह सोच कर कि वह भी अपने परिवार के सदस्य हैं, हमने ही उन को देश की सेवा के लिये मोर्चों पर लगाया हुआ है। अगर इन के पत्र में कोई वास्तविकता हो तो विचार करना चाहिये।

एक बात उन्होंने यह लिखी है कि जितने भी आफ़िसर रैंक के लोग हैं उनको आप

फॅमिली सैपरेशन ग्रलाउन्स देते हैं लेकिन उन के लिये जो दूसरी रैंक के सेना के जवान हैं इस प्रकार के भत्ते का कोई प्रावधान नही है। उन्हें फॅमली सैपरेशन ग्रलाउन्स नहीं मिलता है।

इसी तरह से उन्होंने यह भी लिखा है कि पीस स्टेशन में भी युद्ध का प्रशिक्षरण करने के लिये जब ग्राफिसर्स जाते हैं तो उन्हें उस के लिये स्पेशल ग्रलाउन्स दिया जाता है। लेकिन जवानों को वहां भी उससे वंचित रखा जाता है।

तीसरी बात यह लिखी है कि जिन स्कूलों में ग्राफिसरों के बच्चे जाते हैं, जवानों के बच्चे उन स्कूलों में जाकर प्रवेश नहीं ले सकते। इसके ग्रलावा एक बात उन्होंने यह लिखी है कि जो जवान हिन्दी जानते हैं ग्रौर उसके ग्राधार पर, अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, ग्रपनी पदोन्नति करना चाहते हैं पर क्योंकि वह ग्रंग्रेजी नहीं जानते हैं इस ग्राधार पर उन की पदोन्नति में बाधा होती है। जबकि इसी पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि सरदार स्वंर्ण सिंह कुछ मास पूर्व संसद के ग्रन्दर यह विश्वास दिला चुके हैं कि भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेद नहीं किया जायगा। लेकिन इस प्रकार की स्थिति वहां ग्राज भी है।

एक बात उन्होंने ग्रपने वेतन के सम्बन्ध में लिखी है, उनके शब्द ज्यों के त्यों मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"क्या सैनिक का गुजारा साढ़े बावन रु० से हो सकता है? हम यह मानते हैं कि हमें फ्री राशन प्राप्त होता है फिर भी एक पत्नी व दो बच्चे का ग्रन्न भी इस ग्रल्प वेतन से नहीं खरीदा जा सकता है। उस की शिक्षा ग्रादि पर खर्च तो दूर रहे। मंहगाई भत्ता भी सिविल से 20 प्रतिशत कम प्राप्त होता है। यह क्यों? क्या मंहगाई का प्रभाव हमारे परिवार पर कम पड़ रहा है, या हम इससे प्रभावित नहीं होते?

दूसरी बात यह लिखी है कि जितने भी मोर्चों पर तैनात जवान हैं उनको तीन साल के बाद पीस स्टेशन पर वापिस भेजा जाता है। लेकिन जितने बड़े बड़े मिलिटरी के आफिसर्स हैं उनके लिये निवास की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन हमारे लिये टैंट प्रोवाइड कर दिये जाते हैं ग्रौर माह पूस की सर्दी में हमको उन्हीं टैंटों में रहना होता है। ग्रब बताइये कि ग्रगर हमारे बच्चे ग्रौर हम बीमार न हों तो क्या हो। तो यह जो इस प्रकार का भेद चल रहा है, यह उचित नहीं है।

मेरा कहना यह है कि जिस देश की सीमाग्रों के ऊपर दो बड़े देश शत्रु के रूप में खड़े हों उस देश की सेना के जवानों में इस प्रकार का रोष ग्रौर इस प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा होने लगे यह कोई शुभ लक्षरण नहीं है। इसलिये हम को कुछ थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि माननीय सरदार स्वर्ण सिंह इस बात को सोचें कि जहां हम इतना रक्षा व्यवस्था पर खर्च करते है, 1100 करोड़ रु० हम ने रक्षा व्यय में लगाया है, 500 करोड़ रु० हथियारों को खरीदने के लिये रखा है, तो 1600 करोड रु० जब हम ग्रपने देश की रक्षा व्यवस्था पर खर्च करना चाहते हैं। पर जिनके हाथों में वह होकर हथियार चलने हैं, जिनके माध्यम से हमारे मोर्चों पर देश की रक्षा होनी है, अगर उनके स्वाभिमान की रक्षा हम नहीं कर सकेंगे तो किस तरह से देश के मोर्चों पर जाकर वे जवान लड़ सकते हैं? इस के लिये मेरा सुझाव है कि एक इस प्रकार का कमीशन बनाना चाहिये कि आफिसरों ग्रौर जवानों के बीच में किस तरह से प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रह सकते हैं, दोनों देश की रक्षा के लिये कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इस बात का ग्रध्ययन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

करें। जो उसके सुझाव हों, उनके अन्दर अगर कुछ तथ्य हों, तो उनको कार्य रूप में परिणत किया जाय।

हमारे पड़ोस में एक देश है जिस की सेनाओं से हमारे जवानों को 1962 में मुकाबला करना पड़ा था। क्या सरदार साहब को यह जानकारी नहीं है कि हमारे कुछ जवान जिन को पकड़ कर के चीनी लोग ले गये थे, उन का ब्रेन वाश करने के लिये या उन के मस्तिष्क को अपने अनुकूल करने के लिये क्या शिक्षा देते थे जो उन्होंने आकर यहां बताया, उसमें यह भी कहते थे कि देखो हमारे अफसरों और जवानों में कोई किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। दोनों के पदों में, स्थानों में किसी प्रकार का कोई विशेष भेद नहीं है। पर तुम जिस देश के जवान हो वहां तुम्हारी स्थिति क्या है ? तुम्हारे देश की सेना के अफसरों की स्थिति क्या है ? अगर हमारे जवानों ने अनुशासन में बधे हुए होने के कारण, और हमारे जवानों ने देश भक्ति से प्रेरित होकर अभी तक जिह्वा नहीं खोली है तो बुद्धिमता का तकाजा यह है कि उन के जोभ खोलने से पहले ही उनकी कठिनाइयों को हम अनुभव करें और उनकी कठिनाइयों का समाधान ढूंढे।

जिस तरीके से उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने उस समस्या को टाल दिया था उसी तरीके से आज अपने जवाब में इसको टालने का यत्न न करें। मंत्री महोदय निश्चित रूप से कोई इस प्रकार का आयोग बनायें जो कि हमारे अफसरों व जवानों के सम्बन्धों को और भी अधिक मधुर कर सके।

MR. CHAIRMAN : The hon Minister.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरी अपनी निजी राय यह है कि इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए सुरक्षा मंत्री महोदय जो कि यहां इस समय मौजूद हैं उत्तर दें वह इस को इतने हलकेपन से न लें कि वह अपने विभाग के उप मंत्री से इस का जवाब दिलवायें। बेहतर यह होगा कि वह स्वयं इस की गम्भीरता को समझते हुए उत्तर देने की कृपा करें।

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अगर पहले क्वेश्चंस कर लिये जांय और उस के बाद मिनिस्टर अपना जवाब दें तो ठीक रहेगा।

MR. CHAIRMAN : That is the proddure that is being adopted.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.R. KRISHANA) : I will try to answer some of the points raised by Shri Prakash Vir Shastri. In case I am not able to do justice, then I have got two stalwarts, my seniors who will be able to come to my rescue.

We are glad that often things which are concerned with Defence, particularly, the welfare of the troops are being discussed in this House, it helps the Defence Ministry and it also helps to eradicate some of the evils which must have crept in due to various reasons in the Defence Forces. Almost everybody in this House knows that our Defence forces are based on the pattern of the British system.

SHRI RANJIT SINGH (Khalilabad) : What a shame !

SHRI M.R. KRISHANA : My hon. friend is more knowledgeable than myself. He should not say that is a shame.

SHRI RANJIT SINGH : Shame to the pattern.

SHRI M R. KRISHANA : Because if he were to know the real facts existing in Defence forces, there are certain past pratices which cannot be forgotten. Civilians may forget but a man who has served the Defence forces should not forget the facts. As a matter of intrest and for the informati-

on of the House I can say that at one time for a strength of 6000 British troops here were about 18000 followers and later on for a strength of 12000 British troops there were 40 000 followers. If I could give a small break-up, a Major General was entitled to have 50 followers and a colonel was entitled to have 40 followers and a Captain was allowed to have 20 followers. This was the pattern of the troops in this country before Independence or even earlier. Later on, when Indians become officers, many of these things have been changed and still some continue. But, as everybody would admit, it is not very easy for any changes to be brought about rapidly in the Defence forces. Even if you want to reduce certain things which are not essential, you cannot do it with a pen overnight. If I can only give you what changes have taken place after Independence, the House will be really satisfied with the way in which the Defence Ministry was progressing. I can certainly give credit to the officers to be without certain facilities which have been enjoyed or which are supposed to be enjoyed even to-day by many other countries which had the British Rule. Many of our officers and men to-day serve in places which are most inhospitable and they are serving in a very difficult terrain. The officers--fortunately I think that is the tradition of the Indian officer-do not differentiate, they do not like to have more comfort like many other officers in the world who would not go to the field if they are not given certain facilities Inculding ice creams and various other comforts. Therefore, the treatment that the officers are giving to the Jawans to-day cannot be questioned and there is nobody in this House nor outside who would say that the treatment which the jawans are geeting from the officers is in any way inferior or something to be questioned or doubted.

Officers have realised that they have to work with their own people; and they also know the contribution that the jawans are making to this country and this country's defence forces. Therefore, nobody will even remotely think that the jawans-whether they are in the Air Force or the Navy or the Army-are ill-treated by the officers.

In this connection, I would like to give only a few facts. Regulation No. 344 of the Army Regulations prohibits the employment of any Government servant for private service. It is concerning not only jawans and Government servants. It also prevents the use of animals which belong to the Government. It also prevent and prohibits the use of any thing which goes to the defence forces Right from 1948, the Army Chiefs have been speaking in conferences on this point. There are various letters written to almost every commander that any misuse of the privileges which are given to the officers will be severely dealt with. I can give the date also. These instructions have been issued and they are in force, right from October, 1948 where the Army Chief has said that if any of these people are engaged in any work other than specified, even while assisting the officers, such work should not detract their basic work which is, the training and the various other kinds of drills which adds to make the soldier a fighting machine. He has to fight. His basic requirement is to fight for the country. And, if anything is done to disturb that arrangement, the concerned officer will be dealt with severely.

The hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri has raised this point. He had also raised this in December, 1968, in a speech. I could give him the action taken against some of the officers who have misused this facility.

I think some of the officers who have been punished are of the rank of Lieutenant Colonels and my hon. friend will agree that Lieutenant-Colonels are not small officers. One of the colonels has been even dismissed because he has used one of the Government servants for his farm. My hon. friend was mentioning about that particular case perhaps.

SHRI RANJIT SINGH : One has been caught doing it.

SHRI M. R. KRISHNA : Two officers have received the severe displeasure of the Army Chief apart from one who was dismissed. This means really very severe

[Shri M. R. Krishna]

punishment has been given to the senior officer.

SHRI RANJIT SINGH : It means nothing. It does not even go on record unless he says it is to go on record.

SHRI M. R. KRISHNA : I do not want to educate my hon. friend on this matter. At the time of promotion and various other things, these are the things which would come in the way. Even if the officer has got the merit to get the promotion some of these things will never be allowed to go unchecked and the officer will have to be punished for misuse. Therefore, at present, there are very few facilities being given to the officers. Particularly, in the forward areas, the officer definitely needs some service in order to carry some of the equipments in the forward areas and certainly jawans are provided, and that is a part of their duty which the jawans are supposed to contribute. If there are any instances of misuse and if these are reported to the Defence Ministry inculding the Army Chief, Air Chief or Naval Chief, they will not tolerate this. There are sufficient instructions already given to the various formations and if there is any deviation or any slackness on the part of any Officer Commanding and if he allows this kind of thing to happen, he will be dealt with seriously. The three instances which I have given about three senior officers are, I take it, quite enough for the House to be convinced that the Defence Ministry and Armed Forces are not willing to allow these things to happen. Officers are given certain facilities and they are expected to use them properly. Wherever they misuse them, they will be severely dealt with. I would definitely appeal to the Hon. Members that if there are any authentic cases of this type, they can definitely send them to the Defence Minister and they will be attended to with all seriousness. Except this, I have nothing more to add.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह बड़े दुःख और शर्म की बात है कि हमारे देश में जो देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करते है और अपने प्राणों की आहुति देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं देश की खातिर, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है। मैंने स्वयं इस चीज को अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली से असम मेल जो बरौनी जाती है और बरौनी से असम मेल आती है उस में हमारे जवान और अफसर दोनों यात्रा करते हैं। एक दिन नहीं बार बार मैंने देखा हैं कि जवानों से कुली का काम वे लेते हैं, उनसे चाय मंगवाने का काम लेते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि मन्त्री महोदय भी वहां जा कर इसको अपनी आंखों से देखें। आप भी जा कर इसकी जांच करें।

दूसरी बात यह है कि जहां से मैं आया हूं, दानापुर से, जो पटना जिले के अन्दर है और जहां कटोनमैंट बोर्ड है, वहां फौजी जवानों से जमीन खोदने का काम लिया जाता है और खाना बनवाने का काम लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसकी आप इनक्वायरी करवायें। यह बड़े ही दुःख और शर्म की बात है कि जिन्हें देश की सुरक्षा के लिये बहाल किया जाता हैं उन से इस तरह के काम लिये जायें। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जवानों के अन्दर हीन भावना घर करती जा रही है और इसको दूर करने के लिये और उनके तथा अफसरों के बीच सदभावना, समता, अपनापन, भाईचारा आदि के सृजन के लिए क्या कोई निश्चित योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ? अगर ऐसी कोई योजना नहीं है तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाने और उसको कार्यान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री तुलसी दास जाधव (बारामती) : चीन–भारत और पाकिस्तान–भारत युद्ध काल में जिन्होंने देश के लिये अपने धर्म का निर्वाह किया और जो करना चाहते हैं, ऐसे बहादुर सैनिकों से इस तरह का अपमानजनक बरताव

करना कहां तक उचित है ? आपने कहा है कि हम बीस बाईस साल से इसकी कोशिश कर रहे हैं । मेरे जिले में कई सैनिक हैं । उन्होंने भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन युद्ध में अपनी जानें दी हैं उन्होंने मुझे लिखा है कि उनको अपमान-जनक जीवन बिताना पड़ रहा है । उनको देखने वाला कोई नहीं है । उनकी फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है । उनको जिस तरह का बरताव मिलना चाहिये, नहीं मिलता है । इतनी बड़ी सेना है । उसको ठीक बरताव मिले और उसकी सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, यह हम सब का कर्त्तव्य है । आपने कहा है कि आपने आर्डर दे दिये हैं । लेकिन उनका इम्प्लेमेंटेशन कहां तक होता है क्या कभी आपने इसको देखा है ? आप लोगों का काम है कि आप गुप्त रीति से इसकी जांच करें कि उनके साथ इस तरह का बरताव तो नहीं हो रहा है । मैंने बाहर के मुल्कों में देखा है, रूस में देखा है, अफसर और जवान दोनों एक जगह काम करते हैं, लेकिन जब शाम को जायेंगे, सिनेमा या थियेटर में जायेंगे, तो दोनों को एक ही जगह एक ही टेबिल पर देखा है । दोनों में कोई भेदभाव नहीं था । इतना यहां पर हो या न हो, यह दूसरी बात है, लेकिन घर में काम करने के लिये उन को भेजा जाये, यह ठीक नहीं है । अगर उन के घर में काम करने की सुविधा देनी हो, तो दूसरे सर्वेन्ट्स रखे जायें, लेकिन सैनिकों से घर का काम नहीं लेना चाहिये ।

तीसरा सवाल यह है कि अफसरों को आप चाहे ज्यादा तनख्वाह दें, ताकि वे अपने यहां नौकर की व्यवस्था करें, लेकिन सैनिकों के लिये यह अपमानित जीवन की बात नहीं होनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस व्यवस्था को कब दूर करेगी और यदि ऐसा करने में कुछ दिक्कत हो तो उसका क्या कारण है ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : जिस देश में मन्त्री और नौकरशाह अपने निजी कर्मचारियों का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिये हमेशा करते आये हैं और अभी भी कर रहे हैं, वहां अगर पलटन के अफसर ऐसा ही बर्ताव अपने जवानों के साथ करें तो इस में कोई आश्चर्य की चीज नहीं है । फर्क इतना है कि जहां मन्त्री और नौकरशाह निजी कर्मचारियों का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिये करते हैं तो उस से पैसे की बरबादी होती है, लेकिन जहां पलटन के अफसर जवानों से अपने घर का काम कराते हैं तो उससे देश के संरक्षण का मामला पैदा होता है, क्योंकि इस से उन के मनोबल को तोड़ने का काम होता है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा—उन्होंने अभी जो आंकड़े यहां पर रखे है कि अंग्रेजी जमाने में मेजर जनरल 50 आदमी नौकर के रूप में अपने साथ रखता था, करनल 40 रखता था, कैप्टन 20 रखता था, लेकिन अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि उस को खत्म कर दिया है......

श्री मं० रं० कृष्ण : अब वह लोग नहीं रख सकते हैं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : लेकिन यह असलियत है, मन्त्री महोदय के आंकड़े गलत हैं, सभी अफसरों के घरों में कई जवान अलग अलग कामों पर लगे हुए हैं, किसी को आर्डरली कहा जाता है, किसी का कोई और नाम रखा जाता है, कोई वाचमैन है, कोई पानी लाने के लिये हैं, कोई सब्जी लाने वाला है, इस तरह से काम लिया जाता है और यह हकीकत है । अगर आप इन्कार करेंगे तो मैं आपको दिल्ली शहर के कई अफसरों के घर ले जाने के लिये तैयार हूं और इस बात को बताने के लिये तैयार हूं ....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री । सुपर मार्केट के पीछे झोला लिये मिलते हैं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अगर आप चाहें तो कई अफसरों के घर ले जा कर वस्तुस्थिति बताने के लिये तैयार हूं ।

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

मेरा प्रश्न यह है—क्या मन्त्री महोदय ऐसा करने के लिये तैयार हैं कि हर जवान के हाथ में, जैसे आप उसको किट देते हैं, यूनिफार्म देते हैं, बन्दूक देते हैं, एक ऐसी लिखित सूचना देंगे कि जवानों से कोई भी घरेलू काम या निजी काम नहीं कराया जायेगा। यदि फिर भी ऐसा कराया जाता है, तो आपके नियम 344 या जो भी नियम हो, उस के अनुसार यह गुनाह माना जायेगा और जो भी यह गुनाह करेगा उस को उचित सजा दी जायेगी। इस में एक दिक्कत यह भी आती है-जैसा प्रकाशवीर शास्त्री जी ने पत्र पढ़कर सुनाया है—अगर वे शिकायत करेंगे तो वे अफसर उन के पीछे पड़ जाते हैं ....

एक माननीय सदस्य : उन का प्रमोशन नहीं करते हैं। प्रमोशन रोक देते हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हर दृष्टि से उन को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। इस लिये उन के अन्दर हिम्मत आये, उन का मनोबल मजबूत बना रहे, हर जवान के हाथ में ऐसी कोई लिखित चीज़ देने के लिये तैयार हैं।

दूसरा प्रश्न—हमारे यहां अफसर और जवानों के बीच में जो अन्तर हैं -असल में हिन्दुस्तान की सामाजिक परिस्थितियों के कारण यह चीज़ चल रही है और जब तक आप लोग समाज व्यवस्था में रहेंगे, तब तक यह दूर नहीं होगी, इस को तो हमीं लोग कर पायेंगे, लेकिन जिस मुल्क के मुकाबले में आज हमारी पलटन खड़ी है—मोटेतौर पर चीन, उस मुल्क के अफसरों और जवानों के बीच में कोई अन्तर नहीं है, यहां तक कि यूनिफार्म, रहन-सहन और दूसरी चीजों में कोई अन्तर नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ अफसरों और जवानों से बात कर चुका हूं —सन 1962 की लड़ाई में जो लोग पकड़े गये थे, जिनको तिब्बत में प्रिज़नर्ज़ आफ़ वार बना कर ले जाया गया था, उन लोगों ने बताया है-"हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि अफसरों और जवानों में कोई अन्तर नही है, उनके रहन-सहन के मामले में, खान-पान के मामले में, कपड़े के मामले में।" क्या इस दिशा में कुछ कदम आप भी आगे बढ़ाने के लिये तैयार हैं ?

19 hrs.

SHRI RANJIT SINGH (Khalilabad) : This is part of a broader question. We have to consider the entire defence set-up which has not changed for the past 23 years although we have been free all the time. The Britishers had a particular system and they themselves changed it. Firstly, the facts are not given correctly. The system of followers was abolished long before we got independence. When we got independence, it was not the system; as I said, the Britishers themselves had abolished it. We have many different countries before us from whom we take examples or we can study what changes are happening in their systems. Even the British Army has changed so far as the employment of orderlies and batmen is concerned. It is true that we have regulatiouns prohibiting personal or private work. But what is the definition of personal, private work ? As per regulations an orderly can be employed by an officer; the same man is called a batman in war. Sometimes for what is known as a war establishment both an orderly and a batman are authorised one for the purpose of office work, for working as a runner etc. and the other to look after his personal needs. In regard to personal needs. the orderly is authorised to do the the work of the officer himself, for instance, getting his clothes from the dhobi, getting him ready for the parade, polishing his shoe and things like that. But it is a fact thatin our Armed Forces, apart from this work which is authorised for an orderly, there is a lot of personal work being taken by the entire family, including cooking and working on the farms. The hon. Deputy Minister says that an officer was caught and punished. But have things stopped ? I am sorry to say that these things have not stopped; they are increasing. It is in the interest of the Armed Forces that we take some steps

to narrow this gap. The question is not one of passing regulations. The entire social system and the social outlook has to change. We have got a false sense of prestige which we inculcate in the officers right from the time they join as cadets in the Academy; we teach him that he is a class by himself. Previously, there used to be a system where even in the Academy, the cadet used to live almost the same life as the jawan; he also used to do guard duties. Now the guard duties have been abolished in the Academy and it is a very sorry state of affairs. At the same time I say that the officer should look smart; his boots should be well polished. If he himself polishes his boots he is looked down upon because the social system and outlook is such. There is a false sense of status. Is it not high time that these things are done away with ? We have had 23 years of freedom. In other countries changes take place. Almost everybody, whether in Parliament or in Government has passed through compulsory military service; almost every important country has compulsory military service, even Britain had a system somewhat like that. Is it not time that we had a broad-based commission, a defence commission to go into the entire defence set-up of our country ? We asked for a standing committee. The Minister was against it. What is the objection of the Minister to have a commission to study this matter ? They have a commission for every thing else and it gives them its report. They can keep in this commission even high retired military officers and serving military officers and some politicians and some social workers and educationists and it can go into the entire set-up of defence and the mode and method of trainning and recruitment and all these things. What is the objection of the Government to set up such a commission ?

SHRI M. R. KRISHNA : In the first place, I am not prepared to agree that this is a universal thing or that every jawan who has been appointed is there to do domestic service for the officers. That is not correct. Even in that case, every time there is a review, and the entitlement is also brought down. That way also we have now reduced the number of batmen by about 15,000. This is under constant review, and Mr. Ranjit Singh has ably answered my dear friend Mr. Prakash Vir Shastri that this has been a tradition which is going on, and that officers do require a certain amount of service when they are in the field area. That is the purpose for which the regulations have permitted that a jawan can work as a batman provided he is temperamentally fit for that, and also he volunteers to do that type of a thing. Otherwise, no jawan is forced. Suppose if any Member were to bring to the notice of this House that some jawan was forced to do a job which he was not willing to, then that would be really a serious matter which we will take up. Actually, only the volunteers are given as batmen to the officers, and that too, to do the work which is essential and specified.

SHRI GEORGE FERNANDES : Compulsory volunteers !

SHRI M. R. KRISHNA : No; not at all. I definitely would say that the Defence Ministry can take credit for abolishing the system of followers. My friend Shri Ranjit Singh says that the Britishers had abolished the cadre of followers and so on. It is not true. Today, the defence forces of this country are bent upon increasing the teeth, or sharpening the teeth, whatever you may call it-and they want to cut down the tail, that is to say, the followers and so on.

SHRI RANJIT SINGH : 'Followers' means quite a different thing. The Hon. Minister may kindly bear with me for a while. 'Followers' was actually a rank in the armed services previously.

SHRI M. R. KRISHNA : Well, I can also give the history of the various kinds of platoons which were there to do this kind of service which has been abolished. The JCO cadre was created because the Britishers would not like to mix with the Indian jawans, and therefore they wanted an intermediate rank. But that is not the position today. (*Interruption*) Probably, at the time when Shri Ranjit Singh was in the armed forces, he did not like to mix with the jawans, but that is not the condition today.

SHRI RANJIT SINGH : Sir, please excuse me. He has made this remark

[Shri Ranjit Singh]

oftentimes, and the Minister of Defence has also made such remarks sometimes like that. I would like to tell the Minister that I still go for my annual training. I go to my annual training invariably. This time I have received even a warning that if I do not go this time I will be sent an apprehension roll.

SHRI M. R. KRISHNA : That is very good.

SHRI RANJIT SINGH : I would like the Members of your party also to join the Territorial Army at least and serve for a month there, and then they will know the real conditions of the armed forces.

SHRI M. R. KRISHNA : We are happy; if we have Members who are acquinted with these things it becomes much less troublesome for us to answer questions here. If there are enlightened Members here, we welcome them and we would like to give them the information which they need.

Now, about this Commission which has been asked, I think it is not a thing which I can answer, and it is also not necessary for a Commission to go into this kind of thing.

SHRI RANDHIR SINGH : A Commission to enquire into the entire defence set-up.

SHRI M. R. KRISHNA : That is a different thing. As I said earlier, the officers of the defence forces are very keen that they should not always have very comfortable lives when they serve in the forward areas. They are invaded by leeches and they have to suffer in every bad weather. But still they do not like to have any support or help from Jawans. It is a fact; the officer class wants that they should have hard life, similarly as the jawans, so that the need for batmen or orderlies has almost come to be nil, and the regulations are very strict. The commanders in the conference always emphasise this, and whoever is found guilty of misusing the jawans who are definitely for a different purpose--to defend this country and be skilled fighters--will be severely punished. Beyond that, I have nothing more to say.

19.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 3, 1969/Chaitra 13, 1891 (Saka).

Printed at Diamond Printing Press, Jaipur-3